(6)	(7)	(8)
		Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	1 yr. for direct recruits. During the period of probation, the persons appointed shall be required to acquire proficiency in Hindi equivalent to matriculation or the Pragya Examination conducted under the Hindi teaching Scheme of the Central Govt.	Direct recruitment.

(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For Confirmation) 1. Additional Secretary (AD)—Chairman 2. Joint Secretary (AD)—Member. 3. Joint Secretary Territorial Division of the language concerned—member. "*Note*:— The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the commission a fresh meeting of the departmental promotion committee to be presided over by the chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held '	Consultation with Union Public Service Commission. Necessary on cash occassion.

[No.Q/CAD/798/3/93. Pt. II]
U.P.S.C. REF No. F.F.3/6 (2)/93/RR
[No. 1/CAD/94]
TARANJIT S. SANDHU, Under Secy.

सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत का दावा

2473. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1995 के "दि हिन्दू" नामक दैनिक समाचारपत्र में "राफेल, लिंक्स इण्डियाज यू० एन० सीट टू जम्मू एण्ड कश्मीर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अमरीका भारत को यूनाइटेड नेशन्स की सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता दिए जाने का, इस मुद्दे को जम्मू और कश्मीर के मामले के साथ जोड़कर विरोध कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भारत के आन्तरिक मामलों में अमरीका का खुला हस्तक्षेप नहीं है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी सरकार की स्थिति यह है कि वह सुरक्षा परिषद् के सुधार की पक्षधर है और स्थायी सदस्यता के लिए जर्मनी तथा जापान का समर्थन करती है लेकिन उसने अन्य ए[illegible] की चयन-प्रक्रिया के संबंध में कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। इस प्रश्न में उल्लिखित खबर में इस मसले पर अमरीका की असिस्टेंट सेक्रेटरी सुश्री [illegible] की टिप्पणी छपी थी उसके बाद विदेश विभाग द्वारा 10 फरवरी, 1995 को समाचार मार्गनिर्देश जारी किया गया जिसमें अमरीका की स्थिति दोहराई गई और यह स्पष्ट किया गया कि अमरीका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ने जो कुछ कहा था वह यह था कि सैद्धान्तिक रूप से भारत एक सीट के लिए उम्मीदवार तो होगा लेकिन [illegible] के साथ उसके संबंध और कश्मीर समस्या संयुक्त राष्ट्र में इस संबंध में होने वाले किसी भी विचार-विमर्श का अंग बन सकती है।

(ग) और (घ) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होने के नाते अमरीका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पुनर्गठन और विस्तार के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। भारत सरकार का यह मत है कि सुरक्षा परिषद् के विस्तार तथा उसमें औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यदल में होने वाले विचार-विमर्श का इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि किसी देश विशेष के द्विपक्षीय संबंध क्या हैं। क्षेत्रीय आधारों को नए स्थायी सदस्यों के चयन का मानदण्ड नहीं बनाया जा सकता और इस क्षेत्र के देशों की व्यक्तिगत आपत्ति को किसी राज्य द्वारा सदस्यता प्राप्त करने के दावे को रोकने का कारण नहीं बनाया जा सकता।

Visit of Iranian Foreign Minister to India

2474. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether Iran's Foreign Minister, during his recent visit to India, expressed his desire to look forward to collaborative efforts with India, with a view to exploiting the opportunities for trade and industry in the Central Asia; and

(b) if so, the reaction of Government and the steps proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) The Foreign Minister of Iran, Dr. Ali Akbar Velayati, during his visit to India in January, 1995 stressed in his official discussions as well as in his meetings with the representatives of Indian trade and industry the importance of India-Iran cooperation in developing commercial and economic linkages with the Central Asian region. Several specific areas of cooperation came up for discussion including infrastructural development for an access route to the Central Asian region, energy sector, textile sector.

(b) Government are actively seeking to realise the potential of India and Iran cooperating in developing the economic ties with the Central Asian republics. An MOU on Transportation and Transit Facilities was signed during Prime Minister's visit to Tehran in September 1993. Indian official delegations have since visited Iran for technical discussion. As follow-up to the discussions during the Iranian Foreign Minister's visit to India in January this year, a trade and transit agreement is under negotiation. Practical steps for promoting the movement of Indian goods for the Central Asian markets via Iran are also under implementation